

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

दैहरादून: दिनांक: 21 जनवरी, 2006

विषय: मैं 0 अल्टर-श्रीलैब्स प्रा०लि० को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु तहसील रुड़की के ग्राम माधोपुर में कुल 0.432 हेक्टर भूमि क्य करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 256/भूमि व्यवस्था-भूमि क्य दिनांक 1 दिसंबर, 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निरेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मैं 0 अल्टर-श्रीलैब्स प्रा०लि० को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु उत्तरांचल (उ०प्र० जमीदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(v) के अन्तर्गत तहसील रुड़की के ग्राम माधोपुर में कुल 0.432 हेक्टर भूमि क्य करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिवर्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- केता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्य करने के लिये अर्ह होगा।
- केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बम्बक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- केता द्वारा क्य की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्य पिलेख के पंजीकरण वी तिथि से की जायेगी अथवा उसके पाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अनिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की


 (2)

गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्य किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये चिक्य, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्य से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंकरणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- आवेदक स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तरांचल के लोगों को 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन उपलब्ध करायेगा।

7- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निररत करदी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एन०एस०नपलव्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 4- श्री अरुण नेगी निवासी 34 अशोक नगर रुड़की, जनपद हरिद्वार।
- 5- निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तरांचल सचिवालय।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सोहन लाल)
अपर सचिव

✓